E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 5(1): 182-187
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 18-04-2023
Accepted: 20-05-2023

मुकेश कुमार लोछब
Ph.D. शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
मुकेश कुमार लोछब
Ph.D. शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान, भारत

ई गवर्नेंस में डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की भूमिका

मुकेश कुमार लोछब

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i1c.221

सारांश
आज विश्व के विभिन्न देशों में सिमटती दूरियों का प्रमुख कारण सूचना एवं संचार को माना जाता है। सूचना क्रांति से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वहीं ई-शासन ने रही-सही कसर को पूरा कर दिया है। ई-शासन में 'ई' का थ्रैटलेट इलेक्ट्रॉनिक से है। सामान्य रूप से ई-शासन का अर्थ है सरकारी कार्यकलाप एवं परियोजना आदि में सूचना संचार तकनीकी (आईसीटी) का प्रयोग करते हुए लोक-कल्याणकारी राज्य की परियोजना को प्राप्त करना।भारत में ई-शासन का प्रादुर्भाव सरकारी कनेक्शन में तेजी से कंप्यूटरीकरण से शुरू हुआ। विदित हो कि प्रमाणन, स्थायी नौकरी और नौकरी-रहित नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए समाज के अंतिम तक सूचना पहुंच की दिशा में भारत सरकार ने 90 के दशक के अंत में देश में ई-शासन योजना शुरू की थी। उसके बाद, केंद्र सरकार ने भारत में ई-गवर्नेंस को सबसे पहले बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को 18 मई, 2006 को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 भाग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और जंपिंग सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का खाका तैयार किया है।

कूटशब्द: ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, डिजिटल इंडिया

प्रस्तावना

ई-गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों?

ई-गवर्नेंस से कठिन कार्य एवं दक्षताओं एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के तौर पर सब्सिडी का सीधा हितग्राही के बैंक लाभ में जाने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित व्यक्तिकरन को लाभ मिल रहा है या नहीं।
ई-गवर्नेंस द्वारा एक सामान्य डाटा तैयार किया जाता है जिसका उपयोग

विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ और आकर्षक बातचीत मिलती है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को कई सारे संदेश आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सरकार विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ बनाने के दौरान इन आँकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय वापस ले सकती है।

ई-गवर्नेंस से कार्य की लागत में भी कमी आती है। विदित हो कि उद्यम का अधिकांश खर्च कागजों (स्टेशनरी) पर होता है। हालाँकि इसके अलावा सामान्य जनता को अपने घर से किसी सरकारी कार्यालय में आने-जाने में बहुत सा समय और पैसा खर्च करना पड़ता है जबकि ई-गवर्नेंस के द्वारा इन सभी अनुमानों से अनुमान लगाया जा सकता है।

सुशासन के लिए सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम को आसान बनाना आसान होता है ताकि पूरी प्रणाली का अनुकूलन दक्ष विकास किया जा सके। ई-गवर्नेंस इस तरह के अवसर प्रदान कर सकता है।

ई-गवर्नेंस से कार्य या सेवा की दक्षता में कमी की जा सकती है।

ई-गवर्नेंस से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इससे जहां सरकार में लोगों का विश्वास वहीं बिचौलिये या दलालों द्वारा आम लोगों का शोषण भी रुकेगा।

ई-गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों की रचना भी की जा सकती है।

ई-गवर्नेंस के माध्यम से हम अपनी जनसंख्या की शक्तियों का बेहतर लाभ उठाकर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकारी प्रयास

केंद्र सरकार की ओर से ई-गवर्नेंस के विस्तारीकरण की दिशा में कई तरह की पहल की गई हैं। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में अभी तक ई-गवर्नेंस व्यवस्था को पूरी तरह से अमलीजामा नहीं पहना गया है, वे जल्द ही जनता से जुड़े सभी करारों में ई-गवर्नेंस को लागू करने के साथ ही इससे आमजन को जागरूक करवाएं । यहाँ हम उन प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके माध्यम से सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के प्रमाणीकरण का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य आम नागरिकों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की क्षमता, नामांकन और साख सुनिश्चित करना है। व्यस्तता है कि आज 3.47 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स-सीएससी) की मदद से वैकल्पिक सेवाओं को डिजिटल तरीके से देखा जा रहा है। देश की 2.3 लाख ग्राम पंचायतों में सरकारी सीएससी 350 से अधिक सेवाएं तक आम आदमी की पहुंच को आसान बना देते हैं, लोगों पर ग्रामीण इलाकों में। इन केन्द्रों से समाज के उपेक्षित शब्दों का सशक्तिकरण हुआ है और 12 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह ग्रामसम्बन्धी जीव विज्ञान सहित सभी प्राणियों को बढ़ावा मिला है। सी नेएससी महिला स्वाभिमान पहल के माध्यम से महिलाओं में माहवारी के दौरान स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता जागरूकता की है और 204 से अधिक सेनेटरी पैड इकाइयां भी स्थापित की हैं।

डिजिटल इंडिया

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जन-सेवाओं की समूची प्रणाली का रूपान्तरण करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम अनुसूचित किया। इस प्रोग्राम ने ई-गवर्नेंस की परिभाषा को अत्यधिक धरातल पर ला

दिया है। जहां तकनीकी रूप से भिन्न नीति अपनायी गई, वहीं परियोजना आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण आधारित संगठन से सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित वातावरण का विकास हुआ और नागरिकों को कई सामान्य दृष्टि संयुक्त रूप से मिलने लगी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की नागरिक केंद्रित कुछ सबसे महत्वपूर्ण शीर्षकों के नोट्स देखे जा सकते हैं-

- **डायरेक्ट लाभ अंतरः** डायरेक्ट लाक्ष अंतरण सरकार की ओर से दिए गए लाभ को सीधे जुड़े बैंक खाते में अंतरित करता है। इसके माध्यम से 440 कार्यक्रम को समन्वित किया गया है और 7,33,981 करोड़ रुपये संवितरित हुए जिससे 1,41,677 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- **डिजिलॉकरः** यह नागरिक अपने सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों को पब्लिक क्लाउड में सुरक्षित रखने के लिए निजी स्थान पर कर रहे हैं। वर्तमान में डिजिलॉकर का उपयोग करने वालों की संख्या 2.3 करोड़ है।
- **पीएमजीडी अपना पीएम दिशा**: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मेरी सरकार (MyGov)**: माईगव शेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म करके देश में प्राप्त पूर्ण अभिशासन में मदद करता है जो उपलब्ध सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में नागरिक अपने विचार साझा कर सकते हैं।
- **डिजिटल भुगतानः** कई नए डिजिटल भुगतान उपकरण जैसे भीम एप, भीम, भारत क्यूआर कोड, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सभी संग्रह आदि शुरू किए गए। अक्टूबर 2016 से मार्च 2019 तक डिजिटल भुगतान के लेन-देन सहित भी आपका विवरण 8,000 गुना बदल गया है।
- **जीवन प्रमाणः** इससे पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डिजिटल तरीके से देखने या प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। 2.58 करोड़ पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाण का उपयोग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र भेजा है।
- **जीईएमः** यह आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 9.5 लाख उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं।
- **ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्टः** सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, न्यायिक अदालतों और न्यायिक अदालतों के मुकदमों में ऑटोमेशन को बढ़ावा देता है। इसके तहत केस स्टेट्स, कॉज लिस्ट, कोर्ट नंबर, केविएट सर्किट आदि कई सेवाएं शामिल हैं। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा भी शुरू किया गया, जिसमें सभी निर्देशित न्यायालयों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और गोदाम के माध्यम से सभी भारतीय आँकड़ों को चित्रित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल**: यह एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कई छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधा विकल्प उपलब्ध है और छात्रों द्वारा आवेदन पत्र, स्कूल प्रशासन द्वारा सत्यापन, अधिकारियों द्वारा स्वीकृति और डीबीटी के माध्यम से संवितरण में भी शामिल है।
- **उमंगः** यह एक कई सरकारी ऐप और डेटाबेसेज के साथ बैकएंड एम्बैसिलस के माध्यम से सरकारी सेवाओं पर निर्भर मोबाइल मोबाइल वेबसाइट उपलब्ध है।

- **ई-अस्पतालः** हॅस्पीटल डीजेनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के 20 से अधिक मॉड्यूल के माध्यम से मरीजों का पंजीकरण, एपिडी, फ्रेम, ब्लड बैंक जैसी गतिविधियों के लिए आसान हो जाता है। वर्तमान में 322 अस्पताल ई-अस्पताल से जुड़े हुए हैं।
- **ई-नामः** ई-नाम कार्यक्रम के तहत 16 राज्यों और 2 केन्द्रित प्रदेशों में 585 कृषि मंडलों का समन्वय ही डिजिटल भुगतान सेवा के साथ किया गया है।
- **देशव्यापी नेटवर्कः** सरकार ने ई-गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से देशव्यापी संचार नेटवर्क के रूप में एनआईसी एनीट नेटवर्क की शुरुआत की।
- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्कः)** सरकार ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो 10जी बैकबोन के माध्यम से व्यापक तकनीकी स्तरों पर राष्ट्रीय नेटवर्क की पहुंच है। यह देश के प्रमाख खोज और अकादमिक सम्बद्धता की तेज गति की स्थितियाँ भी उपलब्ध हैं।
- **डेटा केंद्रः** यह पहल सेवाओं के साथ ई-गवर्नेंस, वेब पोर्टल और वेबसाइट के लिए ठोस, सुरक्षित और लचीले विकल्प उपलब्ध हैं। स्मरणीय हो कि डेटा केंद्र और राष्ट्रीय क्लॉड के माध्यम से वर्तमान में 10,000 विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए सहयोग जारी है।
- **भूस्थानिक (जियोस्पेशियल) तकनीकः** भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) ने स्थान आधारित संपर्क पर ही विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देकर विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं की विशिष्टता को बेहतर बनाया है। उसी समय डिजिटल इंडिया जैसी कार्यक्रम भी प्रभावकारी तरीके से संभव होने के लिए भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करती है।
- **ई-मेल सेवाः** डिजिटल इंडिया अभियान की कार्ययोजना के तहत सरकार सभी आधिकारिक बातचीत के लिए सुरक्षित ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। आज ईमेल सेवा जियो-फेन्सिंग सहित कई तरह की सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। आज की तारीख में 25 मिलियन से भी अधिक उपयोगकर्ता आईडी और 2,000 एप्लीकेशन ईमेल सेवाएं उपयोग करते हैं। लोगों को संचार के इन से और प्रभावशाली तरीके से जोड़ने के लिए एसएमएस (एसएमएस) सेवा की भी शुरुआत की गई है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः** प्रशासन को एक-दूसरी ईकाइयों से जोड़ने और करीब आने का मकसद एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा फैला रहा है। यह सेवा 1995 से ही उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1,852 से भी ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट ठप हो चुकी है और ये सरकारी कामकाज और मांगों का बंटवारा हो गया है। वीडियोकांफ्रेंसिंग का प्रशासन प्रणाली की सभी स्तरों का उपयोग केंद्र व राज्य, राज्य और जिला और तहसील और सरकार और जनता के बीच संयोजन स्थापित करने में व्यापक रूप में किया जाता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कारः सरकार के कर्मियों, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी करार द्वारा जाने वाली, सरकार से सरकार (सरकार से सरकार), सरकार से नागरिक (सरकार से नागरिक), सरकार से व्यवसाय (सरकार से व्यवसाय) की सर्वोत्तम सबसे शुरुआती मान्यता प्रदान करता है।

चुनौतियाँ: इस प्रकार स्पष्ट है कि ई-गवर्नेंस का सुशासन, भ्रष्टाचार को रोकने एवं लोक सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके बावजूद इस क्षेत्र में अभी भी कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- सूचना क्रांति का भारत के ग्रामीण निर्धन लोगों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। यह भी एक तथ्य है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों सहित समूची ग्रामीण आबादी को डिजिटल रूप में सक्षम समाज में रूपान्तरित करना एक बड़ी चुनौती रही है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने वाले भारतीय समाज में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधा प्राप्त वर्ग एवं इस सुविधा से वंचित वर्ग के मध्य एक नया विभाजन देखने को मिल रहा है।
- ई-गवर्नेंस के समक्ष कुछ तकनीक संबंधी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिसमें गोपनीयता, साइबर हमलों से सुरक्षा आदि प्रमुख हैं।
- स्थानीय भाषाओं, वेब सर्वर का विकास, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के मानव संसाधन को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षकों का अभाव है।

निष्कर्षत

कहा जा सकता है कि ई-शासन प्रणाली से जहाँ एक ओर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक-सामाजिक एवं अन्य विभिन्न मुद्दों का सरलीकरण एवं सूचनाओं का तीव्र स्थानांतरण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यह नागरिक एवं सरकार के मध्य नागरिक-मित्र सरकार का आधार भी निर्मित करती है। लेकिन इस दिशा में अभी और भी काम करने की जरूरत है। हालाँकि सरकारी प्रयास सराहनीय है, बावजूद इसके लिए कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- ऐसे समावेशी विकास पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों और रोजगार के अवसरों को अपेक्षित बढ़ावा दे सकें।
- इसके अतिरिक्तफ़ देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
- ई-गवर्नेंस को लागू करने संबंधी तकनीकी अवसंरचना, महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान, कुशल मानव संसाधन एवं ई-साक्षर नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। डिजिटल असमानता को दूर करते हुए सभी को समान सूचना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण और इंटरनेट के उपयोग के प्रसार के साथ ही लोगों से जुड़ी सरकारी योजनाओं में अगर पर्याप्त रूप से और जन उपयोगी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए तो यह विकेंद्रीकरण के लिहाज से क्रांतिकारी नतीजे ला सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और 'ई-शासन' को बढ़ावा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब आम नागरिक इसका उपयोग सहजता से कर पाने में सक्षम हो।

संदर्भ

1. ऑकोट, उमा आर. डब्ल्यू ओ (2005), 'गुड प्रैक्टिसेज इन ई-गवर्नेन्स: मैन इ यूज एण्ड चैलेंजिंग, ई-गव, अगस्त, 2005.
2. ओई सी. डी. (2003), द ई गवर्मेन्ट इम्प्रेटिंव, पेयरस् ओ. ई. सी. डी. ई- गवर्मेन्ट स्टडीज, आई. एस. बी. एन. 92-94-10117-9
3. आई. एस ओ. इन्टरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैण्डडाइजेशन 2010 इन्टरनेशलन इन्स्टीट्यूट फॉर कम्प्यूकेशन एण्ड डवलपमेन्ट www.licd.org
4. ई-गवर्नेन्स के मुद्दे और चुनौतियाँ (15. फरवरी 2011) MIS 3G 2011 में मुद्दों और चुनौतियों

(स्रोत: ई-सेवा सूचना लेखा परीक्षा सरकार द्वारा एक ई-शासन पहल) www.icisa.cag.gov.in

5. ई-शासन, सैद्धांतिक नींव और व्यावहारिक निहितार्थ डोब्रिका साविश (जुलाई 2006) मांट्रियल
6. ई-गवर्नेन्स के मुद्दे और चुनौतियाँ 15 फरवरी 2011. ई-गवर्नेन्स 2011 wordpress.com
7. एन. एस. कलसी, रवि किरन और अनुसूचित जाति वैदय (2009) प्रभावी ई-गवर्नेन्स भारत में सुशासन, बिजनेस रिसर्च इंटरनेशनल समीक्षा पत्र वॉल्यूम 5-101 पी.पी 12-229